(c) No. Sir, The complaints are being attended to properly.

(d) and (e) The questions do not arise in view of reply at (a) and (c) above.

दिल्ली में गांवों का शहरीकरण

770. **श्री रामजीलाल**: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों में रह रहे लोगों की संख्या कितनी हैं;

(ख) क्या सरकार ने जनसंख्या वृद्वि को देखते हुए दिल्ली के गांवों को शहरीकृत करने का निर्णय लिया हैं;

(ग) अब तक शहरीकृत गांवों का ब्यौरा क्या हैं;और

(घ) शहरी करण किए जाने के लिए शेष गावों का ब्यौरा क्या हैं ?

शहरीकार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) दिल्ली में गांवों का शहरीकरण जनसंख्या के आधार पर नहीं किया जाता है ।

(ग) एम सी डी,एन डी एम सी तथा दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शहरीकृत गांवों के ब्यौरे निम्रानुसार हैं:-

एन सी डी.....135 गांव

दिल्ली छावनी बोर्ड.....6 गावं

एनडीएमसी.....1 गावं

(घ) एम सी डी और डीडीए ने सूचित किया है कि क्रमश: 15 तथा 68 गांवों को शहरीकृत किया जाना प्रस्तावित हैं ।

दिल्ली में नर्सिग होमों के लिए भूमि

771. **श्री रामजीलाल**: क्या शहरी कार्य और रोज़गार मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में नर्सिग होमों के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित की थी;

(ख) यदि हां,तो ब्यौरे सहित ऐसी रियायत देने के क्या कारण हैं;

(घ) समाज के गरीब वर्ग के लिए अब तक 25 प्रतिशत पलंग उपलब्ध न कराने वाले नर्सिग होमों के नाम क्या-क्या हैं;और

(घ) समाज के गरीब वर्ग के लिए प्रति वर्ष 25 प्रतिशत पलंग उपलब्ध न कराने वाले नर्सिग होमों के विरूद्व सरकार ने क्या कार्रवाई की हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) डी.डी.ए.ने सूचित किया है कि दिल्ली में नर्सिग होम के लिए प्लाटों का आबंटन खुली नीलामी के माध्यम से किया गया है ।

(ख) से (घ) उपर्युक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता ।

"सब के लिए आवास" हेतु निर्धारित लक्ष्य

772. **श्री लाला लाजपत राय**: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000 तक " सब के लिए आवास" कराने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया हैं ;

(ख) यदि हां,तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई हैं;

(ग) क्या वर्ष 2000 तक लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा और मुम्बई "दिल्ली,चेन्नई,कलकत्ता और हैदराबाद में आवासीय समस्या के संबंध में क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है;और

(घ) यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) शासन के राष्ट्रीय एजेण्डा के भाग के रूप में सरकार का लक्ष्य प्राप्त वर्ष 2 मिलियन अतिरिक्त आवास यूनिटें उपलब्ध कराने का हैं । इसमें से 7 लाख यूनिटें शहरी क्षेत्र में होगी ।

(ख) 12.2.99 तक 2,15,769 यूनिटों की मंजूरी दी गई है । लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) प्रगति की हाल ही में की गई समीक्षा से पता चलता है कि 7 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य तकरीबन पूरा हो जाएगा । तथापि ये अधिकाशंत: राज्य सरकारों द्वारा हुडकों को समय पर परियोजनांए प्रस्तुत करने का निर्भर करता है । भारत सरकार ने मुम्बई,दिल्ली,कलकत्ता,चेन्नई तथा हैदराबाद के बारे में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है ।